भीलवाड़ा कार्यालय से इन्फॉर्मेशन टैक्नॉलजी विभाग में यौन शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया

शिकायत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शासन सचिव व कई वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई है

- दावा है कि सात हस्ताक्षरों वाली यह शिकायत विभाग की महिला कर्मचारियों ने की है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
- शिकायत भीलवाड़ा के सूचना प्रौद्योगिकी कार्यालय के सहायक प्रोग्रामर के खिलाफ है।
- आरोप है कि उक्त प्रोग्रामर महिला कर्मियों को अश्लील मैसेज भेजता है, यौन संबंध का दबाव डालता है और विरोध करने पर काम में कमी निकाल कर प्रताड़ित करता है।

भीलवाड़ा, 8 जुलाई (निसं)। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में सैक्सुअल हरैसमैंट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। विभाग में कार्यरत एक सहायक प्रोग्रामर के खिलाफ सात हस्ताक्षर वाली इस शिकायत ने विभाग की नींद उड़ा दी है।

राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शासन सचिव सहित विभाग के आलाधिकारियों को भेजी गई शिकायत में विभाग में कार्यरत सहायक प्रोग्रामर के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि यह शिकायत विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों द्वारा की गई है। कहा जा रहा है कि विभाग में सहायक प्रोग्रामर के नाम को लेकर खौफ का माहौल है, उक्त कर्मचारी पर महिला कर्मचारियों को अश्लील मैसेज भेजकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाए जाने और विरोध करने पर कार्य में कमी निकाल कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने जैसे गंभीर आरोप भी शिकायत में लगाए गए हैं। यही नहीं, उक्त कर्मचारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार में लिप्त होने और कार्यस्थल पर नशीले पदार्थों का सेवन करके आने जैसे भी कई आरोप शिकायत में लगाए गए हैं। सी.एम.ओ. तक शिकायत पहुंचने के बाद विभाग ने मामले में इंटरनल जांच के आदेश दिए।

भीलवाड़ा विभाग के संयुक्त निदेशक पवन ननकानी ने शिकायत की पुष्टि करते हुए बताया कि जयपुर से भेजी गई शिकायत में 7 हस्ताक्षर किए गए हैं। लेकिन विभागीय जांच में विभाग में कार्यरत किसी भी महिला कर्मचारी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर होने की पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में अब तक इस मामले में शिकायतकर्ता सामने नहीं आया है। हालांकि विभाग मामले की गहनता से जांच कर रहा है, जिसकी रिपोर्ट जयपुर पेश की जायेगी।

मॉस्को में प्र.मंत्री मोदी का भव्य स्वागत

- उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव प्र.मंत्री मोदी की अगवानी करने खुद एयरपोर्ट पर पहुँचे।

मॉस्को, 8 जुलाई (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रूस की राजधानी मास्को पहुंचने पर देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। मोदी का विमान स्थानीय समयानुसार पौने तीन बजे मॉस्को के वनुकोवो अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उतरा। रूसी सरकार ने उन्हें दुर्लभ सम्मान देते हुए प्रथम उप प्रधानमंत्री श्री मंतुरोव को श्री मोदी की अगवानी के लिये भेजा। गौरतलब है कि यह पहला मौका था कि जब श्री मंतुरोव ने किसी विदेशी शासनाध्यक्ष की हवाईअड्डे पर अगवानी की है। इससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मॉस्को यात्रा के दौरान श्री मंतुरोव से कनिष्ठ उप प्रधानमंत्री ने उनकी अगवानी की थी। मोदी को रूसी सशस्त्र सेनाओं की एक संयुक्त टुकड़ी ने सलामी गारद पेश की और इसके बाद श्री मंतुरोव श्री मोदी के साथ एक ही कार में सवार हो कर होटल के लिए रवाना हो गये।

'कांग्रेस के विधायक, नेता प्रतिपक्ष को अपना लीडर ही नहीं मानते, शैडो कैबिनेट कैसे सफल होगी'

संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस की शैडो कैबिनेट पर कटाक्ष किया

- पटेल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है।
- पटेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है और भाजपा की भजनलाल सरकार के एतिहासिक कार्यों से कांग्रेस बौखला गई है।

जयपुर, 8 जुलाई (का.सं.)। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस के शैडो कैबिनेट बनाने के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायक दल में कोई तालमेल नहीं है और सदन के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीच वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही है।

पटेल ने कहा कि कांग्रेस के विधायक नेता प्रतिपक्ष को अपना नेता ही नहीं मानते। ऐसे में शैडो कैबिनेट कितनी सफल होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। भाजपा की भजनलाल शर्मा सरकार निरंतर जनहित में ऐतिहासिक फैसले ले रही है। अगर कांग्रेस की वाकई जनहित करने की मंशा है तो सदन में सत्ता पक्ष का जनहित के मामलों में समर्थन करे और सदन की कार्यवाही में सहयोग करे।

पटेल ने कहा कि कांग्रेस केवल सदन की कार्यवाही में व्यवधान पहुंचाने और विकास कार्यों से जुड़े विधेयकों को अटकाने के लिए शैडो कैबिनेट बनाएगी तो हम इसका पुरजोर जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब कांग्रेस के मंत्री जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए। कांग्रेस सरकार के मंत्री खुद अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे और मुख्यमंत्री गहलोत ने चुप्पी साधे रखी। अब जबकि प्रदेश की भजनलाल सरकार जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए दिन रात जुटी है तो कांग्रेस के नेताओं में बौखलाहट है।

जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रदेश की जनता ने भाजपा को बहुमत देकर स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस जनता की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई। पिछले पांच साल प्रदेश में अराजकता का माहौल किसी से छिपा नहीं है। युवा, किसान, महिलाएं और दलितों पर पिछले पांच सालों में जमकर अत्याचार हुए और कांग्रेस आपसी फूट और गुटबाजी में उलझी रही। पूर्व की कांग्रेस सरकार में पूरे पांच साल पेपर लीक और महिला अत्याचार के मामलों से प्रदेश की देशभर में चर्चा रही।

हेमंत सोरेन पर एक बार फिर गिरफ्तारी की तलवार लटकी

चार दिन पहले ही मु.मंत्री पद की शपथ लेने वाले हेमंत सोरेन की रिहाई के खिलाफ ई.डी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है

- कथित जमीन घोटाले में मनी लॉण्डरिंग के आरोप में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद सोरेन को जेल भेज दिया गया।

नई दिल्ली, 8 जुलाई। कथित जमीन घोटाले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। सोरेन की जमानत के फैसले के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। सोमवार को ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

बता दें कि कथित जमीन घोटाले में मनी लॉण्डरिंग के आरोप में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद सोरेन को जेल भेज दिया गया। तब चंपाई सोरेन ने झारखंड के सीएम का पद संभाला था। बाद में झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए सोरेन को रिहा कर दिया था। जेल से वापस आने के बाद हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है। आज सोरेन सरकार की कैबिनेट का विस्तार भी हुआ। उनके साथ 11 और मंत्रियों ने शपथ ली। हालांकि, मंत्रिमंडल के विस्तार के ही दिन सोरेन के लिए मुश्किलें खड़ी कर देने वाली खबर सामने आ गई। अब ईडी ने झारखंड हाई कोर्ट के जमानत वाले फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

लोकसभा चुनावों के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक निश्चित समय के लिए जमानत मिली थी। बाद में 1 जून को केजरीवाल को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा। उस समय हेमंत सोरेन को जमानत नहीं मिली। इस दौरान लोगों ने कई तरह के सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। हालांकि, अब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं और सोरेन जमानत पर बाहर आ गए हैं। बाहर आने के साथ ही उन्होंने झारखंड की कमान अपने हाथों में ले ली है। हालांकि, ईडी के सुप्रीम कोर्ट में जमानत के खिलाफ अर्जी दायर करने के बाद एक बार फिर से सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में चंपाई सोरेन ने राज्य की सत्ता संभाली। अब चंपाई सोरेन को एक बार फिर से कैबिनेट में शामिल करते हुए जल संसाधन विभाग और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। चंपाई सोरेन के साथ ही जेएमएम कोटे से 6 मंत्रियों ने शपथ ली है।

संविदा कर्मी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ही अदालत ने मामले में राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता कपिल प्रकाश माथुर को याचिका की प्रति दिलाते हुए 15 जुलाई तक जवाब पेश करने को कहा है। जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश राम अवतार मेहरिया की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रमाकांत गौतम ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की प्लेसमेंट एजेन्सी के जरिए एक जुलाई, 2022 को ब्लॉक समन्वयक के पद पर संविदा कर्मी के तौर पर अजमेर जिले में नियुक्ति हुई थी। नियुक्ति के बाद से वह अपने कर्तव्यों का उचित तरह से निर्वहन करता आ रहा है। इस बीच गत 6 जून को स्थानीय विकास अधिकारी ने याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करते हुए उसके स्थान पर अन्य संविदा कर्मी को नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिए। इसे चुनौती देते हुए याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के संबंधित पद पर काम करने को लेकर कोई शिकायत नहीं है और उसने उचित तरह से अपने कार्य को पूरा किया है। इसके अलावा नियमानुसार संविदा कर्मी को उसी स्थिति में पद से हटाया जा सकता है, जब तक संबंधित पद पर नियमित भर्ती से अभ्यर्थी नियुक्त नहीं हो जाता। ऐसे में एक संविदाकर्मी को हटाकर उसके स्थान पर दूसरे संविदा कर्मी को नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए याचिकाकर्ता को हटाने के आदेश को रद्द किया जाए।

'यह स्वीकृत तथ्य है कि, नीट यू.जी. परीक्षा का पेपर लीक हुआ है'

सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रूप अपनाया है और सरकार से यह पता करने को कहा है कि पेपर लीक से कितनों को फायदा हुआ है

- सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार, 11 जुलाई को करेगा। कोर्ट ने बुधवार (10 जुलाई) की शाम 5 बजे तक नैशनल टैस्टिंग एजेन्सी (एन.टी.ए.), केंद्र सरकार और सी.बी.आई. को मामले में हलफनामा पेश करने के लिए कहा है।

नई दिल्ली, 8 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने विवादों से घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट-यूजी' 2024 को रद्द करने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सख्त रूप अपनाया है और सरकार से यह पता करने को कहा है कि पेपर लीक से कितनों को फायदा हुआ है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले में दायर कुल 38 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि पेपर तो लीक हुए हैं, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि हम लीक की प्रकृति पर विचार कर रहे हैं।

सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने सख्त रुख अपनाया और कहा, ''पेपर लीक पर विवाद नहीं किया जा सकता। हम इसके परिणामों पर भी विचार कर रहे हैं। हम एक आदर्श दुनिया में नहीं रहते हैं, लेकिन दोबारा परीक्षा पर निर्णय लेने से पहले हमें हर पहलू पर गौर करना होगा क्योंकि हम जानते हैं कि हम 23 लाख छात्रों के भविष्य की बात कर रहे हैं।''

सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार, 11 जुलाई को करेगा। कोर्ट ने बुधवार (10 जुलाई) की शाम 5 बजे तक एनटीए, केंद्र सरकार और सीबीआई को मामले में हलफनामा पेश करने को कहा है। कोर्ट ने एनटीए से उन उम्मीदवारों की पहचान करने को कहा है जिन्हें नीट-यूजी पेपर लीक से फायदा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से उन केंद्रों/शहरों की पहचान करने को भी कहा है जहां पेपर लीक हुआ है।

इससे पहले सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि गलत कृत्य करने वाले कितने छात्रों के परिणाम रोके गए हैं। कोर्ट ने कहा कि हम ऐसे लाभार्थियों का भौगोलिक विवरण जानना चाहते हैं। सीजेआई ने पूछा कि मान लें कि सरकार परीक्षा रद्द नहीं करेगी, लेकिन पेपर लीक करने वालों की पहचान करने के लिए क्या करेगी? क्योंकि जो हुआ उसे हमें नकारना नहीं चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा कि हमारी साइबर फोरेंसिक टीम के पास किस तरह की टेकनोलॉजी है। क्या हम सभी संदिग्धों का एक डेटा तैयार नहीं कर सकते? इस परीक्षा में जो हुआ, वह आगे नहीं हो, क्या हम इसके लिए कदम नहीं उठा सकते? एनटीए ने कहा कि अगर परीक्षा की पवित्रता खत्म हो जाती है, तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। यदि दागी और बेदाग को अलग करना संभव नहीं है, तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना ही होगा। सीजेआई ने यह भी कहा कि अगर पेपर लीक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हुआ है, तो यह जंगल में आग की तरह फैल सकता है और बड़े पैमाने पर लीक हुआ हो सकता है।

कोर्ट ने कहा कि हम पूरी प्रक्रिया जानना चाहते हैं। दूसरी मामले में दर्ज एफआईआर की प्रकृति और पेपर लीक कैसे फैला इसकी भी जानकारी चाहते हैं। सीजेआई ने पूछा कि केंद्र और एनटीए ने गलत काम करने वालों की पहचान करने के लिए अब तक क्या-क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की कि जिस किसी ने भी परीक्षा के नियमों का उल्लंघन किया है, उसे वहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने इस बावत क्या कदम उठाए हैं।

इन याचिकाओं में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) की पांच मई को हुई परीक्षा में गड़बड़ी और कदाचार का आरोप लगाया गया था और इसे रद्द कर फिर से आयोजित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

राहुल गांधी मणिपुर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वरिष्ठ नेता भी हैं।

कांग्रेस ने "एक्स" पर की गई एक पोस्ट में कहा है, "हिंसा (प्रारम्भ होने के) बाद उनकी तीसरी मणिपुर-यात्रा जनता के निमित्त उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।" गांधी पहली बार मणिपुर उस समय गये थे, जब मणिपुर में नस्ली हिंसा शुरु हुए कुछ ही दिन हुए थे। मणिपुर में 3 मई 2023 से नस्ली हिंसा शुरु हुई। उन्होंने अपनी "भारत जोड़ो न्याय यात्रा" भी जनवरी 2024 में मणिपुर से ही शुरू की थी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सबसे पहले जिरिबाम हायर सेकण्डरी स्कूल में स्थापित राहत-शिविर में गये।

राज्य कांग्रेस अध्यक्ष कीशम मेघचन्द्रा ने पत्रकारों को बताया कि जिरिबाम के राहत शिविर में रह रहे लोगों ने वहां रहने के अपने अनुभव राहुल गांधी के साझा किए।

मेघचन्द्रा ने कहा, "उन्होंने (राहुल) उनसे उनकी जरूरतों के बारे में पूछा। एक लड़की ने गांधी से कहा कि इन लोगों को देखने न तो प्रधानमंत्री आये हैं और न मुख्यमंत्री। उसने गांधी से यह भी अनुरोध किया कि वे इस मामले को संसद में रखें।" प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जिरिबाम में हजारों लोग गांधी से मिलने के लिये घरों से निकल आये तथा कुछ लोग तो उनसे बात करते समय रोने लगे। राहुल गांधी जिरिबाम से असम के सिल्चर होते हुए इम्फाल हवाई अड्डे पर आये तथा वहाँ से सड़क मार्ग से चरचाँदपुर जिले के हुईबाँग गाँव में स्थापित राहत शिविर में पहुँचे। वहाँ भी उन्होंने शिविर में रहने वाले लोगों से बातचीत की।

मेघचन्द्रा ने कहा, "राहुल गांधी की इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को सहयोग-सम्बल देना तथा वहाँ की जमीनी स्थिति का आकलन करना है। उनकी यह यात्रा दर्शाती है कि पार्टी हाल ही की हिंसा में प्रभावित हुये लोगों की चिन्ताओं के समाधान के कृतसंकल्प है।"

राहुल गांधी लौटने से पहले, इम्फाल में राज्यपाल अनुसुया उइकी से भी भेंट करेंगे।

मणिपुर में मैतेई तथा कुकी समुदायों के बीच गतवर्ष मई में शुरू हुई नृजातीय हिंसा में अब तक 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी हैं।

गांधी की इस उपद्रवग्रस्त राज्य की यह यात्रा वहाँ के लोगों को यह दर्शाने का गम्भीर प्रयास है कि वे इस सर्वाधिक संकट की घड़ी में पीड़ित लोगों के साथ खड़े हैं। राहुल का उद्देश्य उस उपेक्षा को भी देशवासियों के सामने लाना है, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ भाजपा ने इस राज्य और उसकी जनता के प्रति दिखाई है। मोदी ने न तो इस राज्य की यात्रा की है तथा वे मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी साधे रहे हैं, और संसद में भी इस मुद्दे पर गंभीरता से नहीं बोले हैं तथा मणिपुर पर बोलने की विपक्ष की सतत माँग की अनसुनी और अनदेखी करते रहे हैं।

भारत में आधी वयस्क जनता हार्ट-अटैक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अभिनव दृष्टिकोण रखने की त्वरित आवश्यकता पर बल देते हैं। उनका मानना है कि शारीरिक सक्रियता को सभी के लिए सुलभ, आर्थिक रूप से वहनीय और सुखद बनाने में इतनी सामर्थ्य है कि ऐसा करने से गैर संक्रामक रोगों में महत्वपूर्ण कमी हो सकती है और आबादी को एक स्वास्थ्यकर तथा तुलनात्मक रूप से अधिक लाभकारी एवं ऊर्जान बनाया जा सकता है।

वैसे, वैश्विक तौर पर 31 प्रतिशत वयस्क शारीरिक सक्रियता के तय स्तरों को पूर्ण करने में विफल रहते हैं, लेकिन भारत में यह आंकड़ा 49.4 प्रतिशत के चौंकाने वाले स्तर तक बढ़ गया है। पाकिस्तान जैसे भारत के पड़ोसी देश के कामगारों में भी फिज़िकल एक्टीविटी का ऐसा ही 45.7 प्रतिशत का स्तर रहा है, हालांकि भूटान (9.9 प्रतिशत) और नेपाल (8.2 प्रतिशत) के आंकड़े इस संबंध में विशेष रूप से कम हैं।

अनुमानों से संकेत मिलता है कि यदि वर्तमान ट्रैण्ड जारी रहा तो वर्ष 2030 तक भारत में निष्क्रिय वयस्कों का प्रतिशत 59.9 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।

डब्ल्यू.एच.ओ. गाइडलाइन्स में यह नुस्खा बताया गया है कि वयस्कों को हर सप्ताह कम से कम 150 मिनिट्स तक ब्रिस्क वॉकिंग या साइक्लिंग जैसी मध्यम से तीव्र फिज़िकल एक्टीविटी या 75 मिनट तक की तीव्र एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। घर के काम या खेलों में सक्रिय भागीदारी जैसी कोई भी शारीरिक गतिविधि डब्ल्यू.एच.ओ. की गाइडलाइन्स के ही अन्तर्गत आती है, जिससे स्वास्थ्य ठीक रहता है।

डब्ल्यू.एच.ओ. महानिदेशक डॉ. तेद्रोस एडनॉम घेब्रिएसस इस बाद पर दुःख व्यक्त करते हैं कि कैंसर हृदय रोग और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों पर शारीरिक गतिविधियां बढ़ाने के माध्यम से काबू नहीं पाया गया। वह इस करैन्ट ट्रैण्ड में बदलाव को लेकर वैश्विक नेताओं का आव्हान करते हैं कि इस उद्देश्य के लिए नए सिरे से समर्पण के साथ ही निर्णायक कार्रवाई की जाए।

शारीरिक सक्रियता को दुनियाभर में प्रोत्साहिक करने और शरीर की निष्क्रियता से संबद्ध हैल्थ खतरों को कम करने के लिए मजबूत नीतियां और फण्डिंग में वृद्धि महत्वपूर्ण हैं।

डब्ल्यू.एच.ओ. रेखांकित करता है कि नियमित शारीरिक व्यायाम डायबिटीज़ को 17 प्रतिशत, हृदय रोग व स्ट्रोक को 19 प्रतिशत, डिप्रैशन व डिमैंशिया को 28 से 32 प्रतिशत और विभिन्न प्रकार के कैंसर्स को 8 से 28 प्रतिशत सहित कई बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को विशेषतौर र कम करता है। अनुमान है कि 4 से 5 मिनियम वार्षिक के मौतों के आंकड़े को अधिक सक्रिय ग्लोबल पॉपुलेशन के माध्यम से संभवतः जा सकता है।

इन गंभीर आंकड़ों के बावजूद थोड़ा आशावादी होने के भी कारण हैं क्योंकि रिपोर्ट में यह विशेष उल्लेख किया गया है कि फिज़िकल एक्टीविटी के मामले में विभिन्न देशों ने प्रगति की है। वर्ष 2030 तक 22 देश शारीरिक असकिरूता में 15 प्रतिशत कमी का लक्ष्य अर्जित करने जा रहा है। पिछले दशक में करीब आधे देशों ने इस मामले में प्रचार दर्शाया है, जिससे संकेत मिलता है कि समेकित प्रयास और रणनीतिक हस्तक्षेप सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं।

शारीरिक निष्क्रियता के सर्वव्यापी मुद्दे के समाधान के लिए स्थानीय संदर्भ वाली ऐसी बहुआयामी रणनीतियां बनाने की जरूरत है, जिनसे सक्रिय जीवन शैली को प्रोत्साहन मिलता हो और जिनसे अन्ततः दुनियाभर में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़े।

अन्नाद्रमुक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जयललिता के शासनकाल में शानदार थी, उन्हें लोकसभा चुनावों के दौरान तीसरे सबसे बड़ी पार्टी को इस शर्मनाक स्थिति में लाने के लिए कोसा।

शशिकला ने कहा कि यह ऐसा समय है, जब पार्टी को बचाने के लिए उन्हें बीच में आना पड़ा और उन्होंने ऐलान किया कि वे अन्नाद्रमुक के समर्थकों को एकजुट करने के लिए राज्यव्यापी दौरे पर निकलेंगी।

ज्योतिर्मठ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बहिन प्रियंका गांधी ने भी इन आरोपों के विरुद्ध अपने भाई का बचाव किया है।

प्रियंका ने कहा, "राहुल हिन्दुओं के खिलाफ कभी नहीं बोल सकते। उनकी टिप्पणीयों का लक्ष्य भाजपा और उसके नेता थे।"

पंजाब में दो समूहों के बीच अंधाधुंध गोलीबारी, 4 की मौत

गुरदासपुर, 8 मई। पंजाब के गुरदासपुर जिले में दो समूहों के बीच पुरानी रंजिश के चलते हुई गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना रविवार रात बटाला के श्री हरगोबिंदपुर के लिघांवाला चौक पर हुई। दोनों समूहों में कुल 13 लोग थे और सभी विठवान गांव के रहने वाले हैं। बटाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एस.एस.पी.) अश्विनी गोटयाल ने बताया कि गोलीबारी में दोनों समूहों के दो-दो लोगों की मौत हुई है।

उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान बलराज सिंह, शमशेर सिंह, बलजीत सिंह और निर्मल सिंह के तौर पर हुई है।

पुलिस ने बताया कि घटना में आठ लोग घायल हुए हैं और उन्हें अमृतसर के एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक सभी घायल खतरे से बाहर हैं।

'राहुल गांधी 2004 से 2014 के बीच कभी भी देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे'

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो इसलिए, क्योंकि राहुल गांधी के लिए पद और सत्ता कोई मायने नहीं रखती

- रेवंत रेड्डी ने कहा कि भले ही राहुल गांधी तब पी.एम. नहीं बने, लेकिन अब कांग्रेसियों को उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए जुटना होगा।

नई दिल्ली, 8 जुलाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2004 से 2014 के बीच कभी भी देश के प्रधानमंत्री बन सकते। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी के लिए पद और सत्ता कोई मायने नहीं रखती। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यह बात कही। सोमवार को वह राज्य के पूर्व सीएम वाईएसआर रेड्डी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भले ही राहुल गांधी तब पीएम नहीं बने, लेकिन अब कांग्रेसियों को उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए जुटना होगा। रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ही कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में जीत हासिल हुई।

पूर्व सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी की 75वीं जयंती के मौके पर रेवंत ने कहा कि उन्होंने जो कल्याणकारी योजनाएं लागू की थीं, वह हमारे लिए प्रेरणा बनी हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही के चुनाव में हमने 6 गारंटियां लॉन्च की थीं और इसकी प्रेरणा हमें उनके कार्यकाल में किए गए कामों से ही मिली थी। रेवंत रेड्डी ने कहा, मुझे याद है कि जब 2009 में लगातार दूसरी बात कांग्रेस की सरकार बनी थी तो वाईएसआर का कहना है कि राहुल गांधी को पीएम बनना चाहिए। राहुल गांधी के पद पर आने से पहले ही वाईएसआर हमें छोड़कर चले गए। अब उन्हें पीएम बनाने के लिए कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी चाहिए।

अविभाजित आंध्र प्रदेश के वाईएसआर मुख्यमंत्री रहे थे। 2004 से 2009 के उनका कार्यकाल काफी चर्चित रहा था। वह 2009 में दोबारा चुनाव जीतने के तीन महीने बाद ही हेलिकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे। रेड्डी ने कहा कि वाईएसआर ने आंध्र प्रदेश में पदयात्रा निकाली थी, जिससे सरकार की वापसी हुई थी। इसी तरह राहुल गांधी ने भी वाईएसआर से प्रेरणा लेते हुए यात्रा निकाली और उसके नतीजे में तीन राज्यों में सरकार बनी। रेड्डी ने कहा, राहुल गांधी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। नेता विपक्ष के तौर पर उनका काम शानदार है। वह पीएम बनने से एक ही कदम दूर हैं। देश उनके ही नेतृत्व में विकास करेगा।

इस दौरान उन्होंने वाईएसआर रेड्डी के बेटे जगनमोहन पर भी निशाना साधा। रेवंत ने कहा कि वाईएसआर के असली उत्तराधिकारी वे हैं जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग गांधी के नेतृत्व के खिलाफ जाते हैं, वे वाईएसआर के वंशज नहीं हैं। इस अवसर पर रेड्डी ने वाईएसआर की एक फोटो प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क, मंत्री श्रीधर बाबू, एआईसीसी प्रभारी दीपा दास मुंशी, पूर्व राज्यसभा सांसद केवीपी रामचंद्र राव, विधायक, एमएलसी और पार्टी के नेता मौजूद थे।

प्रदेश के 13 जिलों में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कई और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, दौसा, करौली, जयपुर, डूंगरपुर जिलों में कहीं-कहीं पर भारी बारिश दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश सुरोत, करौली में 137 मिलीमीटर और पश्चिमी राजस्थान के तारानगर, चूरू में 141 मिलीमीटर दर्ज की गई है। इसके अलावा श्रीगंगानगर में 84, पिलानी में 41.6 मिलीमीटर बारिश हुई।

मौसम केंद्र जयपुर ने आज प्रदेश के 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो आज जयपुर, अजमेर, दौसा, अलवर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, सीकर, नागौर, झालावाड़, कोटा और बारां जिलों में कहीं-कहीं पर बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मेघगर्जन व वज्रपात के साथ 20 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी।

मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश में मानसून की गतिविधियां धीमी होने की संभावना जताई थी। हालांकि, 10 जुलाई को प्रदेश के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केन्द्र के अनुसार उत्तरी जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केन्द्र के अनुसार मानसून की ट्रफ लाइन उत्तर की ओर से शिफ्ट हुई है। इसके असर से उत्तरी जिलों में भारी बारिश होगी। मौसम केन्द्र के अनुसार आठ और नौ जुलाई को बारिश की गतिविधियों में कम आएगी। इसके अलावा दस जुलाई को फिर से भारी बारिश का दौर शुरू होगा।

'राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600